



साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378



पेज 03

सरकारी विभागों में बंद
होगी बैंकडोर एंट्री

सोमवार, 05 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026

हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08

आबादी के साथ
बढ़ रहा वर्कलोड

वर्ष : 02 अंक : 31 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए

www.shaharsatta.com



पेज

04

खुरचन : निवेश करो, प्रोफेसर की कुर्सी पाओ

कैंसर का इलाज हाईटेक रोकथाम का सिस्टम बीमार

राज्य में कैंसर अस्पताल बढ़े तो कैंसर भी बढ़ा, कैंसर की रोकथाम में विभागीय कसावट फेल

ढाई साल में 17,611 कैंसर मरीज सामने आए, मुंह का कैंसर सबसे आगे

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव

कैंसर... नाम सुनते ही किसी भी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सवाल यह कि जिस प्रदेश में पिछले एक दशक में कैंसर के इलाज का पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया, अत्याधुनिक मशीनें आ गईं, निजी और कॉरपोरेट अस्पताल तेजी से बढ़े और इलाज की नई-नई तकनीक उपलब्ध हो गई, उसी प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार चिंता क्यों बढ़ा रहे हैं? राज्य के उपलब्ध आंकड़े इस चिंता को और गहरा करते हैं। 1 अप्रैल 2024 से जून 2026 के बीच 17,611 कैंसर मामले सामने आए। इनमें 4,465 मामले अकेले मुंह के कैंसर के हैं। यानी कुल मामलों में सबसे बड़ी संख्या मुंह के कैंसर की है। ऐसे में सवाल सिर्फ अस्पतालों और इलाज की सुविधा का नहीं रह जाता। सवाल यह भी है कि बीमारी पैदा करने वाले जोखिमों, खासकर तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर निगरानी कितनी मजबूत है? और यहीं से कहानी अस्पतालों की चारदीवारी से निकलकर सरकारी निगरानी तंत्र तक पहुंचती है।



रायपुर। रायपुर के प्रायः सभी जाने-माने ऑनकोलॉजिस्ट्स से चर्चा करने पर एक भयानक सच सामने आता है। छत्तीसगढ़ में कैंसर के 85 प्रतिशत से अधिक मरीज गरीब तबके से हैं, जिनमें आधे से अधिक मामले मुंह, गले या फेफड़े के कैंसर के हैं। इसका स्पष्ट कारण सिगरेट, पाउच और गुटखा बनाने वाली कंपनियां हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास नमूने लेने वाले 63 से अधिक अधिकारियों का अमला तैनात है, इसके बावजूद बाजार में खुलेआम बिक रहे तंबाकू युक्त प्रोडक्ट के पिछले तीन वर्षों में विभाग ने एक भी सैपल नहीं लिया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नामचीन ब्रांड्स से लेकर स्थानीय और डुप्लीकेट गुटखा निर्माताओं पर लगाम कसने के लिए राज्य में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक तुकाराम मुंडे जैसा कोई सख्त

और निष्ठावान अधिकारी नहीं है? यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि जहां मुंबई में 'तुकाराम' जैसे अधिकारी बड़े-बड़े रसूखदारों पर शिकंजा कस रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 'चहेते' अधिकारी ऐसी कंपनियों को लैब टेस्ट में आसानी से हरी झंडी दे रहे हैं।

विभाग का मूल कर्तव्य मिलावटी खाद्य पदार्थों, दवा दुकानों और गुटखा उत्पादों की नियमित जांच कर आम जनता को गंभीर बीमारियों से बचाना है। लेकिन पिछले ढाई-तीन दशकों से यह विभाग राज्य में केवल डॉक्टरों और दवा दुकानों की संख्या बढ़ाने का जरिया बनकर रह गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या केवल सिगरेट और गुटखा-पान मसाला से ही नहीं, बल्कि बाजार में बिक रही मिलावटी खाद्य वस्तुओं की वजह से भी तेजी से बढ़ रही है।

प्रोडक्ट को सेफ रखने
मिला रहे जहरीला पदार्थ

बता दें इस विभाग का गठन का उद्देश्य बड़ा पवित्र था। इसे आमजनों के जानमाल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन, मिलावटी खाद्य पदार्थों और गुटखा में मैग्नेशियम कार्बोनेट जैसा जहरीला पदार्थ के प्रतिशत की जांच कर लोगों को गंभीर बीमारियों से महफूज करने वाला महकमा ही बेकार साबित हो रहा है। विभाग छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों और दवा दुकानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है। मिलावटी चीजें और बिना मानक के केमिकल मिलाने से ही सुबे में कैंसर के केसेज तेजी से बढ़े हैं। जैसे गुटखा में मैग्नेशियम कार्बोनेट जैसा जहरीला पदार्थ इसलिए मिलाया जाता है कि गुटखा की लाइफ बढ़े, आपस में चिपके मता।

रायपुर से जिलों तक पहुंचा कैंसर उपचार

सरकार कैंसर उपचार को जिला स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में 3 सरकारी कैंसर अस्पताल और 2 सरकारी रेडियोथेरेपी यूनिट संचालित हैं। इसके अलावा 26 जिलों में District Day Care Chemotherapy Centres यानी DCCC चल रहे हैं। पांच और जिलों में DCCC शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य मरीजों को बार-बार रायपुर जैसे बड़े कैंसर सेंटर तक आने की जरूरत कम करना है। स्वास्थ्य केंद्रों में मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन स्क्रीनिंग के बाद की तस्वीर साफ नहीं है। कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई? कितने संदिग्ध मिले? कितनों को आगे जांच के लिए भेजा गया? कितने मरीजों में कैंसर की पुष्टि हुई? और कितने मरीज उपचार केंद्र तक पहुंचे? उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्क्रीनिंग से लेकर शासकीय अस्पताल तक मरीज के पहुंचने की पूरी कड़ी का डेटा व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शुरुआती स्तर पर कैंसर पकड़ने की मुहिम का वास्तविक परिणाम सामने नहीं आ पाता।

अस्पताल बढ़े, मरीज भी बढ़े

रायपुर में कैंसर उपचार की सुविधाओं का विस्तार पिछले 10-15 वर्षों में तेजी से हुआ है। AIIMS रायपुर में 2013 से Radiation Oncology सेवाएं संचालित हैं। आज यहां आधुनिक रेडिएशन तकनीकों के माध्यम से कैंसर का उपचार किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी कैंसर उपचार के बड़े संस्थान सामने आए। BALCO Medical Centre ने 2018 में 170 बेड की oncology facility के साथ कैंसर उपचार में बड़ा विस्तार किया। Sanjeevani लंबे समय से कैंसर उपचार की सुविधा दे रहा है। मेदांता कैंसर अस्पताल भी रायपुर में अपनी नई संस्था खोलने की तैयारी कर रहा है। BALCO Medical Centre के अनुसार वहां करीब 65 हजार मरीजों का उपचार किया जा चुका है। करीब 12 हजार बड़ी सर्जरी और 80 हजार से अधिक chemotherapy sessions किए जा चुके हैं। यानी इलाज का ढांचा मजबूत हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीमारी रोकने का ढांचा भी उसी अनुपात में मजबूत हुआ है?

दस साल पहले टेलीकोबाल्ट, आज
आधुनिक रेडिएशन तकनीक

मेकाहारा में कैंसर उपचार की तकनीक में भी बड़ा बदलाव आया है। करीब दस वर्ष पहले यहां कैंसर के लिए मुख्य रूप से टेलीकोबाल्ट और ब्रैकीथेरेपी जैसी सुविधाएं थीं। आज IMRT, IGRT और VMAT जैसी आधुनिक तकनीकों से रेडिएशन उपचार किया जा रहा है। इन तकनीकों की मदद से कैंसर प्रभावित हिस्से पर अधिक सटीक रेडिएशन देने और आसपास के सामान्य ऊतकों को बचाने की कोशिश की जाती है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांट के माध्यम से ब्रैकीथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है। विभागीय जानकारी के अनुसार मेकाहारा में प्रतिवर्ष करीब 24 हजार मरीजों का कीमोथेरेपी उपचार और करीब 25 हजार मरीजों का रेडिएशन उपचार किया जाता है। मरीज की जरूरत के अनुसार इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। पात्र मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है।

स्टेज-1 और 2 में बेहतर संभावना, स्टेज-4 में चुनौती बड़ी

कैंसर की गंभीरता को सामान्य तौर पर चार चरणों में देखा जाता है। शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान होने पर उपचार के बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है। वहीं स्टेज-4 में बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है और कई मामलों में शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मरीजों द्वारा शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना कैंसर उपचार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुंह में लंबे समय तक रहने वाला घाव, आवाज में बदलाव, निगलने में परेशानी, असामान्य रक्तस्राव, शरीर में असामान्य गांठ या लंबे समय से समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है।

सरकारी से चार गुना मरीज निजी संस्थानों में

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से जून 2026 के दौरान 3,901 मरीजों का उपचार सरकारी संस्थानों में, जबकि 15,497 मरीजों का उपचार निजी संस्थानों में दर्ज हुआ। यह आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है।

- क्या सरकारी कैंसर उपचार की क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में कम है?
- क्या मरीज बेहतर सुविधा के लिए निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं?
- क्या सरकारी अस्पतालों में प्रतीक्षा और सीमित संसाधन इसकी वजह हैं?
- क्या दोनों आंकड़े अलग-अलग reporting categories को दर्शाते हैं?

इन सवालों का स्पष्ट जवाब तभी मिलेगा जब सरकार सरकारी और निजी संस्थानों के unique patients, treatment episodes, referrals और bed capacity का अलग-अलग डेटा जारी करे।

केस-1 : तीन महीने का समय बताया
था, नौ महीने बाद भी जंग जारी

रायपुर निवासी विजय आनंद चंद्रवंशी को पेंक्रियास (अग्न्याशय) में कैंसर है। परिजनों के मुताबिक, शुरुआत में डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताते हुए लगभग तीन महीने का समय बताया था। लेकिन इसके बाद करीब नौ महीने गुजर चुके हैं और विजय लगातार इलाज करा रहे हैं। इस दौरान उन्हें 12 से 15 बार कीमोथेरेपी दी जा चुकी है। परिजनों के अनुसार, इलाज के दौरान अब डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए यह तक कहा है कि अब ज्यादा दिन की उम्मीद नहीं है और मरीज को घर ले जाएं। परिवार ने विजय का इलाज अलग-अलग जगह कराया—पहले हैदराबाद, फिर बालको अस्पताल और इसके बाद AIIMS में भी इलाज कराया गया।

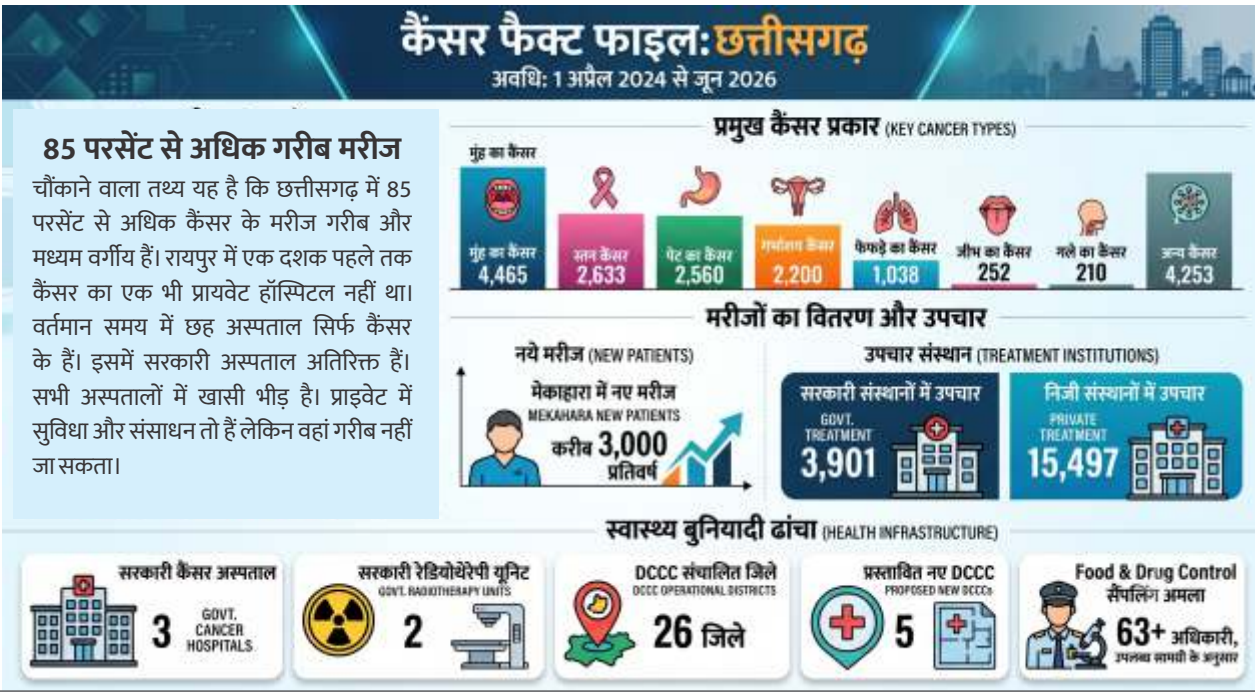
केस-2 : आयुष्मान में इलाज, लेकिन
Carboplatin के लिए बाजार का सहारा

खैरागढ़ निवासी 60 वर्षीय नीरज सिंह का इलाज रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक, बायोप्सी के बाद कैंसर की पुष्टि हुई और डॉक्टरों ने कुल तीन कीमोथेरेपी कराने की सलाह दी। अब तक दो कीमो हो चुकी हैं, जबकि तीसरी कीमो इसी महीने 20 तारीख को प्रस्तावित है। परिजनों का कहना है कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाला Carboplatin 450 mg/45 ml (Kemocarb) इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिला। पहली कीमो के दौरान यह इंजेक्शन आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल से नहीं मिल पाया, जिसके बाद परिवार को इसे बाहर से खरीदना पड़ा। इसके लिए करीब 3,100 रुपए खर्च करने पड़े। दूसरी कीमो के दौरान भी यही स्थिति बनी और संबंधित इंजेक्शन बाजार से खरीदना पड़ा। अब तीसरी कीमो सामने है और परिवार को चिंता है कि इस बार भी यदि Carboplatin 450 mg/45 ml अस्पताल में उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्हें फिर अपनी जेब से दवा खरीदनी पड़ेगी।



कैंसर की दवा का संकट: Carboplatin
450 mg भी बाजार से गायब

कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाला Carboplatin 450 mg/45 ml (Kemocarb) इंजेक्शन रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आसानी से उपलब्ध नहीं होने की शिकायत सामने आ रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि जहां यह इंजेक्शन मिल रहा है, वहां प्रिंट रेट से अधिक कीमत मांगी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्धता नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को इसे बाहर से महंगी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि Carboplatin आवश्यक कैंसर कीमोथेरेपी दवाओं में शामिल है। वर्ष 2026 में इसकी सप्लाई में कमी को लेकर आधिकारिक स्तर पर भी चिंता सामने आई है। कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने Carboplatin 10 mg/ml के सीलिंग प्राइस में बढ़ोतरी भी की है। सवाल यह है कि जब यह दवा कैंसर मरीजों के लिए जरूरी है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क मिलनी चाहिए, तो सरकारी अस्पतालों में इसकी पर्याप्त उपलब्धता क्यों नहीं है? क्या दवा की कमी के कारण मरीजों को निजी बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है?



निवेश के नाम पर मुख्यमंत्री, अधिकारी जनता का धन विदेश यात्रा में फूंक रहे: वंदना राजपूत

शहर सत्ता/रायपुर। विदेश जाने के नाम पर सरकार में बैठे लोग जनता के धन को विदेश यात्राओं में लुटा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि हकीकत यह है कि इस विदेश यात्राओं काक प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ है। एमओयू हुआ जमीन आवंटन भी हुआ लेकिन धरातल पर पीने तीन साल में न कोई फैक्ट्री नहीं लगी और न रोजगार मिला। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सिंगपुर के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर गये थे। मुख्यमंत्री को नौन-कौन सी कंपनियों से एमओयू हुआ था, सार्वजनिक करे सरकार? छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई से मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी जापान, साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए थे, वहां से कितना निवेश आया सरकार को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए? इसके पहले भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी अमेरिका दौरे पर गए थे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका दौरे पर गए थे लेकिन नहीं बता पाए कि उनके दौरे से राज्य को क्या फायदा हुआ है? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार लगातार निवेश प्रस्तावों और एमओयू के बड़े-बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। अगस्त 2025 में सरकार की ओर से बताया गया था कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 84 कंपनियों से 6.65 लाख करोड़ रू. के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मार्च 2026 में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष ने राज्य में 8 लाख करोड़ रू. से अधिक के एमओयू होने की जानकारी दी। लेकिन सवाल यह है कि एमओयू और प्रस्ताव कितने हुए, यह नहीं-उनमें से वास्तविक निवेश कितना हुआ?

दशगात्र से लौट रही ऑटो की पिकअप से भिड़ंत; 4 मौतें, 4 गंभीर

शहर सत्ता/रायपुर। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम हुए सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ओवरलोड ऑटो और तेज रफ्तार पिकअप की सीधी भिड़ंत में 11 अन्य महिलाएं और ड्राइवर बुरी तरह घायल हैं, जिनमें 4 की हालत बेहद नाजुक है। पुलिस के अनुसार, छिंदिया गांव की रहने वाली 15 महिलाएं एक ही ऑटो में सवार होकर बिलारो गांव से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रही थीं। रात करीब 8 बजे सावारांवा के पास सामने से तेज रफ्तार पिकअप ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठी महिलाएं उछलकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में फुलकुंवर (50), रामबाई (60) और फुलकुंवर (60) ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस से घायलों को तुरंत पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर 4 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बैकुंठपुर रेफर किया गया है। यहां चंदमति पति संतलाल निवासी छिंदिया की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोरिया कलेक्टर और एसपी रात में ही अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों को घायलों के समुचित व त्वरित इलाज के सख्त निर्देश दिए।

भिलाई में जीआईएस-ड्रोन सर्वे से बनेगा डिजिटल जल डेटाबेस

शहर सत्ता/रायपुर। जलभराव, जल निकासी और भूजल संरक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए भिलाई नगर निगम एकीकृत शहरी जल प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है। इसमें ड्रेनेज, वर्षाजल संरक्षण, भूजल रिचार्ज, पेयजल, सीवेज और जल गुणवत्ता को एक साथ शामिल किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग, ड्रोन सर्वे और फील्ड डेटा के आधार पर शहर की जल संरचनाओं और निकासी व्यवस्था का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इससे जलभराव वाले क्षेत्रों और उनके कारणों की पहचान कर सुधार कार्यों की प्राथमिकता तय की जा सकेगी। योजना के तहत 75 से 80 वर्ग किमी क्षेत्र और करीब 350 किमी सड़क व ड्रेनेज कॉरिडोर का ड्रोन सर्वे प्रस्तावित है। सर्वे के आंकड़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर शहर के जल प्रबंधन की एकीकृत तस्वीर तैयार की जाएगी। जीआईएस मैपिंग से पेयजल लाइनों और सीवेज के संभावित क्रॉस-कनेक्शन, लीकेज और संदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। 24 चिह्नित बोरेवेल सहित चयनित स्थानों से पानी के नमूनों की जांच भी कराई जाएगी।

कांग्रेस-प्रभारी सुखदेव भगत 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे

कांकेर जिला-कांग्रेस की बैठक और ‘वोट बचाओ,देश बचाओ’ मार्च में होंगे शामिल



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 6 अक्टूबर की रात रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 7 से 9 अक्टूबर तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कांकेर और दंतेवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। वहीं, दंतेवाड़ा के हितालकुड़म-बारसूर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी लेंगे। सुखदेव भगत 6 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रात में रायपुर में ही रुकेंगे। इस दौरे में संगठनात्मक बैठकों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी प्रस्तावित है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सुखदेव भगत का यह 15 दिनों के भीतर दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा।

7 अक्टूबर: कांकेर में बैठक और मार्च

-सुबह 10 बजे: रायपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे।

-दोपहर 1 बजे: कांकेर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे।

-दोपहर 2 बजे: कांकेर में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च में शामिल होंगे।

मुस्लिम युवाओं को गरबा में जाने लेनी होगी अनुमति

कांग्रेस बोली- वक्फ बोर्ड अध्यक्ष BJP के पिटू, .भाजपा बोली- फतवा जारी करवाना है क्या?



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरबा को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से समिति की अनुमति लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक गरबा में शामिल हों तो मूर्ति पूजा करें, तिलक लगाएं और कलावा बांधें।

उन्होंने युवाओं से अपनी मां और बेटियों के साथ ही गरबा में शामिल होने और दूसरे समाज की महिलाओं के साथ गरबा न करने की अपील की। डॉ. सलीम राज ने कहा कि गरबा में छेड़छाड़ और लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं। उन्होंने नाम बदलकर गरबा में शामिल होने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात भी कही। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज भाजपा की चाटुकारिता के लिए लगातार बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक गरबा में बहुत कम जाते हैं और गरबा समितियां भी गैर-समाज के लोगों को शामिल करने से बचती हैं।

शुक्ला ने कहा कि सलीम राज के बयानों को मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करें कि वे धर्म गुरुओं को उकसाकर क्या छत्तीसगढ़ में कन्हैया कुमार जैसा फतवा जारी करवाना चाहते हैं।



गरबा में जाए तो नियमों का पालन करें - वक्फ बोर्ड

डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से कहा कि गरबा आस्था का विषय है और यह मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं है। जब मूर्ति पूजा नहीं कर सकते तो गरबा में जाने की जरूरत नहीं है। गरबा कोई पर्यटन स्थल या मनोरंजन का केंद्र नहीं है।

कांग्रेस बोली- मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को संज्ञान लेना चाहिए

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सलीम राज भाजपा के पिटू की तरह काम कर रहे हैं। मुस्लिम युवक गरबा में जाते ही नहीं हैं या बहुत कम संख्या में जाते हैं। गरबा में माता की पूजा और मूर्ति पूजा होती है। इसलिए समितियां भी कोशिश करती हैं कि गैर-समाज के लोग इसमें शामिल न हों।

युवा भागीदारी से भाजपा में खलबली : धनंजय सिंह ठाकुर

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा कांग्रेस के चुनाव में 14 लाख से अधिक Gen-Z युवाओं की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का युवा लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। युवाओं की इतनी बड़ी भागीदारी से भाजपा नेताओं में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि भाजपा नेता युवा कांग्रेस के चुनाव पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को युवा कांग्रेस के चुनाव की चिंता छोड़कर उन सवालों का जवाब देना चाहिए, जिनका जवाब प्रदेश का युवा उनसे मांग रहा है। मोदी सरकार के हर साल दो करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ? राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा कहा है? 57 हजार शिक्षकों की भर्ती की स्थिति क्या है? युवाओं के स्वरोजगार के लिए लोन की गारंटी



का लाभ कितने युवाओं को मिला? पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आने वाली कथित अनियमितताओं पर सरकार ने क्या ठोस कार्रवाई की? युवाओं के भविष्य से जुड़े इन सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा नेता कांग्रेस और युवा कांग्रेस पर बयानबाजी कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि सरकार के पास युवाओं के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का प्रयास किया गया है। कुछ स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निर्वाचन प्रभारी ने उन्हें संज्ञान में लिया है। शिकायतों की जांच होगी और यदि कोई अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, शिकायत को दबाना नहीं, उसकी जांच करना और तथ्य सामने आने पर कार्रवाई करना।

धमतरी में गंगाजल पिलाकर धर्मांतरित परिवार की घर वापसी

शहर सत्ता/रायपुर/धमतरी। धमतरी जिले के भटगांव में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। समाज के लोगों ने परिवार पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद करीब एक घंटे तक बैठक चली। बैठक में परिवार से समाज के रीति-रिवाज मानने और हिंदू धर्म अपनाने की सहमति ली गई। इसके बाद तिलक लगाकर, गंगाजल का छिड़काव और गंगाजल पिलाकर परिवार को दोबारा समाज में शामिल किया गया। इसके बाद महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया। परिवार ने कहा कि करीब चार साल पहले अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन अब अपनी मर्जी से वापस हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। यह मामला रूद्री थाना क्षेत्र का है।



तिलक लगाकर, गंगाजल पिलाकर समाज में किया शामिल

संदीप अग्रवाल ने बताया कि सुरेश ध्रुव ने लिखित रूप से भी अपनी सहमति दी है कि वह बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं और आगे अपने पुराने धर्म और समाज के रीति-रिवाजों का पालन करेंगे। सुरेश ध्रुव ने कहा कि उन्होंने करीब चार साल पहले अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपनाया था। अब उन्होंने दोबारा ईसाई धर्म में नहीं जाने और हिंदू धर्म में रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मर्जी से वापस हिंदू धर्म में लौटे हैं। मामले को लेकर करीब एक घंटे तक समाज के लोगों के बीच बातचीत चली। सहमति बनने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।

रायपुर पहुंचे चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ में LJP की होगी एंट्री, चुनाव और SIAR पर कांग्रेस को घेरा



शहर सत्ता।/रायपुर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान रविवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई स्थापित की जाएगी और पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी की जाएंगी। आगामी चुनावों में भी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। छत्तीसगढ़ में पार्टी की इकाई स्थापित होने

के बाद बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि, इस संबंध में फैसला समय और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की इकाई करेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में लोक जनशक्ति पार्टी अपने स्तर पर भी काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन खड़ा करेगी LJP

चिराग पासवान ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई जल्द स्थापित की जाएगी। इसके बाद संगठन में आवश्यक नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि, आगामी चुनाव में पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से बातचीत करने और उनकी बात समझने के लिए वे रायपुर पहुंचे हैं। चुनाव आयोग और SIAR को लेकर उठ रहे सवालों पर चिराग पासवान ने कहा कि, यदि देश के किसी भी मतदाता को चुनाव आयोग पर संदेह है, तो आयोग की जिम्मेदारी है कि वह लोगों का विश्वास जीते। उन्होंने कहा कि, SIAR में जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, वे आम मतदाता नहीं थे। अगर बड़ी संख्या में आम मतदाताओं के नाम काटे जाते तो बड़े स्तर पर आंदोलन देखने को मिलता। कांग्रेस की ओर से चुनावों को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया।

दिव्यांगों के लिए रोजगार, 7 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू

शहर सत्ता/रायपुर।दिव्यांगों को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से 7 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संभल केंद्र, आईडीएमएसटी कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक के पास रायपुर में होगा। आयोजन बीपीसीएल और मा एड एंजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए कुल 20 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 12 पद श्रवण बाधित और 8 पद अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है।चयनित अभ्यर्थियों को 8 हजार से 10 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इंटरव्यू 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।समाज कल्याण विभाग ने पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हों और रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाएं।

कर्ज और बिलजी बिल चुकाने ज्वेलरी शॉप में चोरी

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित श्री लक्ष्मी विनायक ज्वेलर्स में सेंधमारी कर की गई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों विशाल सचदेव और सूरज दीमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, विशाल सचदेव वारदात का मास्टरमाइंड है। महासमुंद में बर्फ की फैक्ट्री शुरू करने के लिए विशाल सचदेव ने लाखों रुपए का कर्ज लिया था। फैक्ट्री नहीं चलने से वह आर्थिक परेशानी में आ गया था। इसके अलावा फैक्ट्री का 7 लाख रुपए बिजली बिल भी बकाया था। कर्ज और बिजली बिल चुकाने के लिए उसने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले सूरज दीमर और एक अन्य साथी के साथ मिलकर ज्वेलर्स में चोरी की प्लानिंग बनाई।आरोपियों ने पहले ज्वेलर्स की रेकी की। इसके बाद 26-27 सितंबर की रात दुकान की दीवार में सेंधमारी की। फिर 29-30 सितंबर की रात दुकान में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा।आरोपियों की पिशाचदेही पर सोने-चांदी और आर्टिफिशियल आभूषण, वारदात में इस्तेमाल कार और एक्टिवा समेत करीब 14.51 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

अग्राथॉन-4.0 में लोगों ने लगाई देशभक्ति की दौड़

शहर सत्ता/रायपुर। अग्रवाल सभा और अग्रवाल युवा मंडल की ओर से रविवार को रायपुर के मरीन ड्राइव में अग्राथॉन 4.0 ‘वेंदे मातरम्-रन फॉर नेशन’ का आयोजन किया गया। राष्ट्रप्रेम, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता के संदेश के साथ हुई इस दौड़ में करीब 3500 से 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और नोएडा से भी प्रतिभागी पहुंचे। इस कार्यक्रम में रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवनीश शरण सिंह ने दौड़ में हिस्सा लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। नगर निगम आयुक्त समबीर मिश्रा, बेमेतरा पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल और भाजपा कोषाध्यक्ष राम गर्ग सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। अग्रवाल सभा अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि अग्राथॉन स्वास्थ्य, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला अभियान है। अग्रवाल युवा मंडल अध्यक्ष सीएस सौरभ अग्रवाल ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, सकरात्मक सोच और राष्ट्रसेवा से जोड़ना है। माई भारत की ओर से अग्रवाल युवा मंडल का सम्मान भी किया गया।आयोजन में समाज के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने सहयोग किया। मीडिया प्रभारी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से लोगों का पहुंचना आयोजन की लोकप्रियता को दिखाता है।

छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू, उमस-गर्मी बढ़ी इस बार 5% ज्यादा बारिश; सरगुजा में 41%, जशपुर-बेमेतरा में 36% कम पानी बरसा



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। अगले 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी हो जाएगी। पिछले साल मानसून की विदाई अक्टूबर के मध्य के आसपास हुई थी, जबकि इस बार सितंबर से ही इसकी वापसी के संकेत मिलने लगे थे। हालांकि, सितंबर के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। वहीं बारिश थमने के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।

पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.6°C कोरबा में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6°C पेण्ड्रा रोड में रहा। प्रदेश में मानसून

सरकारी विभागों में बंद होगी बैकडोर एंट्री

पटवारी-बाबू से लेकर प्यून और ड्राइवर तक के पद लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे



शहर सत्ता/रायपुर।रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों और कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का सिस्टम बदल रहा है। अब विभागों में इन पदों को विभागीय स्तर पर भरने की व्यवस्था को सीमित कर कर्मचारी चयन मंडल के जरिए परीक्षा कराने पर जोर दिया जा रहा है। यानी सरकारी विभागों में बैकडोर एंट्री बंद होगी।कर्मचारी चयन मंडल से परीक्षा के लिए कई विभागों ने अपने भर्ती नियम में संशोधन कर लिया है, जबकि कई में प्रक्रिया चल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व निरीक्षक, पटवारी और सहायक ग्रेड-3 जैसे पदों से लेकर वाहन चालक, प्यून, चौकीदार, माली तक की भर्ती मंडल की परीक्षा से होगी। इस व्यवस्था सामान्य प्रशासन, गृह-पुलिस, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जेल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जल संसाधन, आदिम जाति विकास, समाज कल्याण, संस्कृति, कृषि, उद्यानिकी, खनिज, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सहकारिता और राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद को शामिल किया गया है। इसी तरह ऊर्जा, मत्स्य, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के साथ निगम और सहकारी संस्थाओं के पद भी परीक्षा व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य शासकीय विभाग भी अपने भर्ती नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद उन विभागों की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल से होगी।

सात समूहों में बांटे गए पद

कर्मचारी चयन मंडल ने पदों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और सेवा की प्रकृति के आधार पर सात समूहों में बांटा है। इनमें अभियांत्रिकी सेवा के उप अभियंता, स्नातक-पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के तकनीकी व प्रशासनिक पद, कार्यालयीन एवं आशुलिपिक पद, शैक्षणिक सेवा, वर्दीधारी सेवा, विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवा तथा हाईस्कूल/तकनीकी स्तर के पद शामिल हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल ने अगले साल यानी 2027 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, इसमें कई विभागों का उल्लेख है।

बैकडोर पर उठते रहे सवाल

छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बैकडोर एंट्री को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पूर्व में विभागों द्वारा स्वायत्त रूप से ली जाने वाली सीधी भर्तियों में स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता की कमी, पक्षपात और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे।कई मामलों में बिना प्रतियोगी परीक्षा या केवल साक्षात्कार के आधार पर भर्तियां की गईं। इन अनियमितताओं को समाप्त करने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अधीन केंद्रित कर दिया है।

केंद्रीकृत भर्ती को बढ़ावा मिलेगा

स्नातक स्तर के समूह में सहायक प्रबंधक, श्रम एवं खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, अमीन, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जैसे पद हैं। वहीं सहायक ग्रेड-3, स्ट्रेनो टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और पंजीयन लिपिक जैसे कार्यालयीन पद भी परीक्षा के दायरे में हैं।स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। इसी तरह सबसे निचले शैक्षणिक स्तर वाले सातवें समूह में वाहन चालक के साथ भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली, हमाल, वार्ड बॉय, आया, केयरटेकर, रसोइया, जांच अनुचर, मत्स्य जमादार और वाटरमेन जैसे पद रखे गए हैं। इस व्यवस्था से विभागवार अलग-अलग चयन प्रक्रिया की जगह परीक्षा आधारित केंद्रीकृत भर्ती को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय संस्कृति ज्ञान-परीक्षा में 25 हजार छात्रों ने लिया हिस्सा



शहर सत्ता/रायपुर। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 3 अक्टूबर को पूरी हुई। रायपुर जिले में करीब 25 हजार छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। राजधानी के शासकीय जेआर दानी कन्या स्कूल की करीब 1000 छात्राओं ने भी उत्साह के साथ परीक्षा दी। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है। इसके माध्यम से बच्चों को अनुशासन, बड़ों का सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही जल, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषयों के प्रति भी छात्रों को जागरूक किया जाता है।

सवालों के जवाब दिए। आयोजकों के अनुसार परीक्षा के

जरिए बच्चों में अपनी संस्कृति को जानने और समझने की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जानकारी भी मिलती है। परीक्षा के संचालन में छत्तीसगढ़ प्रभारी डीपी चंद्राकर, रामपाल तिवारी, रविशंकर गुप्ता सहित गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों और स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा। इस दौरान प्राचार्य हितेश दीवान, समिधा उपासने, क्रांति चंद्र, डॉ. वैजयंती गुप्ता, मीनू पांडेय, ज्योति सक्सेना, सुषमा शर्मा सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।

15 अक्टूबर तक ले सकेंगे सितंबर-अक्टूबर का चावल

शहर सत्ता/रायपुर। राज्य सरकार ने

सितंबर-अक्टूबर का चावल एक माह में देने का फैसला लिया था। इसके लिए लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन जो तय समय में राशन नहीं ले पाए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे सभी लोग अब 15 अक्टूबर तक चावल ले सकेंगे। इसके लिए 1 अक्टूबर को ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है।

राशन दुकानदारों तक भी यह आदेश पहुंचा दिया गया है कि अब उन्हें दो माह का चावल 15 अक्टूबर तक देना है। कोर पीडीएस सिस्टम के तहत लोग शहर के किसी भी राशन दुकान से चावल ले सकते हैं। खाद्य संचालनालय की ओर से सभी खाद्य नियंत्रकों और खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में राशन दुकानों को नई समय-सीमा की जानकारी पहुंचा दें। कोई भी दुकानदार लोगों को चावल देने से मना करता है तो उसके खिलाफ



कार्रवाई की जाएगी। छूटे हुए लोगों को हर हाल में सितंबर और अक्टूबर का चावल देना ही होगा। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से तय समय में सभी राशन दुकानों में दो माह का चावल नहीं पहुंचाया जा सका था। इसके बाद ही यह तय हो गया था कि लोगों को चावल लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। चावल आपूर्ति समय पर नहीं होने की वजह से नान के जिला प्रबंधक को भी हटा दिया गया है। अभी नए प्रबंधक त्रिनाथ रेड्डी काम संपाल रहे हैं।

साइबर फ्राँड में फ्रीज खाते 90 दिन में खुल सकेंगे, बैंक को मिला अधिकार छोटे कारोबारियों और आम खाताधारकों को राहत

शहर सत्ता/रायपुर। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्राँड के मामलों में ब्लॉक कराए गए खातों को खुलवाने के लिए खाताधारकों को अब थाना, साइबर सेल और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत, शिकायत दर्ज होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया में 90 दिन के भीतर रोक जारी रखने या हटाने का वैध निर्देश नहीं मिलने पर बैंक खाते से पाबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया निर्धारित शर्तों के अधीन होगी और अदालत का कोई आदेश लंबित होने पर रोक जारी रह सकती है।

साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस पीड़ित के खाते से हुए लेनदेन की कड़ी की जांच करती है। इसके बाद बैंक को सूचना देकर संबंधित खातों पर रोक लगाई जाती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कई बार ठगी की रकम का लेनदेन ऐसे खातों से भी हो जाता है, जिनके धारकों का साइबर ठगी से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ऐसे खातों पर रोक लगने से कारोबार, वेतन और रोजमर्रा के खर्च प्रभावित होते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पान ठेले, सब्जी विक्रेता या छोटे कारोबारी के खाते में कोई ग्राहक 10-20 रुपए का यूपीआई भुगतान करता है। यदि भुगतान करने वाले व्यक्ति के खाते में संदिग्ध लेनदेन हुआ है, तो उस लेनदेन की कड़ी में छोटे कारोबारी का खाता भी ब्लॉक हो सकता है। पुलिस पहले



लेनदेन से अंतिम लेनदेन तक लेयर-6 तक के खातों को रोक सकती है।

ऐसे खाताधारकों को अब तक खाता खुलवाने के लिए थाना और साइबर सेल के चक्कर लगाने पड़ते थे। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत में किसी खाते के किसी खास लेनदेन पर विवाद होने की स्थिति में संबंधित रकम पर रोक और बाकी राशि के इस्तेमाल की अनुमति देने का सवाल उठता है। अदालत ने संबंधित परिस्थितियों में विवादित रकम रोककर बाकी अविवादित राशि के इस्तेमाल की अनुमति देने के सिद्धांत पर जोर दिया।



संपादकीय

- सुकांत राजपूत



हवा में जांबाजी टला बड़ा हादसा

वि परीत परिस्थितियों में अगर विवेक का साथ बना रहे, तो यह किसी त्रासद नतीजों के रुख को भी मोड़ देने में सक्षम साबित हो सकता है। बुधवार को दुबई से इजराइल की राजधानी तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में अगर उसके पायलट कैप्टन स्मित मछार ने हिम्मत के साथ अपने ऊपर हुए हमले का सामना नहीं किया होता, तो विमान में मौजूद एक सौ चौहत्तर यात्रियों के साथ क्या होता, कहा नहीं जा सकता।

खबरों के मुताबिक, उड़ान के दौरान ही मछार के सह-पायलट ने अचानक ही उन पर धारदार चीज से हमला कर दिया और विमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। ऐसे हमले के बाद आमतौर पर व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और उसके बाद संभल सकने वाली स्थितियां भी बिगड़ जाती हैं। मगर इस बात के लिए कैप्टन स्मित की जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम होगी कि गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद उन्होंने अपना साहस कायम रखा और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बेहोश होने से पहले विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया।

दरअसल, सबसे नाजुक वक्त में स्मित मछार का बस यही वह फैसला था, जिसकी वजह से समूचे विमान के यात्रियों की जान बच सकी। हालात भांपते ही अन्य कू सदस्य और अन्य कुछ यात्री भीतर घुसे और हमलावर पर किसी तरह काबू पाया जा सका। विमान किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच सका और इसमें कुछ अन्य यात्रियों ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई।

मगर कैप्टन स्मित ने जिस तरह की कठिल स्थिति में अपनी हिम्मत कायम रखी, कर्तव्य याद रखा, बहादुरी के साथ हमलावर का सामना किया और दरवाजा खोल दिया, उसे एक अविश्वसनीय, लेकिन एक ऐसे सच के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से विमान के सभी यात्री सुरक्षित रहे और एक बड़ी त्रासद घटना से बचा जा सका। स्वाभाविक ही स्मित मछार को आज दुनिया भर में अदम्य साहस की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी काफी प्रशंसा की और उन्हें वास्तविक नायक बताया।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि कैप्टन स्मित को अब विपरीत हालात में विवेक और बहादुरी के एक शानदार उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा और उनका साहस एक प्रेरक-तत्त्व के रूप में काम करेगा। मगर इसके समांतर एक चिंता फिर से उभरी है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ तमाम अभियानों के बावजूद आज भी इसका खतरा कायम है। हैरानी की बात यह भी है कि जहां विमान में कोई हल्का-सा जोखिम पैदा करने वाली वस्तु भी लेकर जाने पर सख्त प्रतिबंध है, वहां खुद सह-पायलट कोई घातक चीज लेकर कैसे घुस गया था। यह बात जांच से ही साफ होगी कि क्या इस घटना में आरोपी सह-पायलट के साथ अन्य लोग भी शामिल थे और क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।

दुनिया आज भी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को अपहृत विमानों के जरिए हुए हमलों की त्रासदी को भूली नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उड़ान के दौरान अगर खुद सह-पायलट ही छिपा आतंकी हो, तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में कैप्टन स्मिथ मछार ने संकट के समय जिस तरह सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया, वह लंबे वक्त तक याद किया जाएगा।

संपादकीय

निवेश करो, प्रोफेसर की कुर्सी पाओ ज्ञान के मंदिर में रेट कार्ड...?

सरकारी विश्वविद्यालयों में “निवेश करो, कुर्सी पाओ” वाले मॉडल की चर्चा जोरों पर है! “असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 लाख और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 55 लाख—अगर नियुक्तियों को लेकर चला नहीं, चर्चाएं सच हैं, तो सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं, पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। यह चर्चा सुनकर शेष बाजार वाले भी पूछने लगे हैं कि “रिटन की कितना है?” कहा जाता है, पहले लाखों लगाइए और फिर वर्षों तक नौकरी करके अपनी “निवेश राशि” वसूलिए।

अगर ये चर्चाएँ महज अफवाह हैं, तो इनका खंडन होना चाहिए। और अगर इनमें स्ती भर भी सच्चाई है, तो यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों का आत्मा पर लगा गंभीर प्रश्नचिह्न है। अविभाजित मध्यप्रदेश में शिक्षा और उच्च शिक्षा के अद्वैत रूप, एतिशेकर शुक्ल आज होते, तो शायद इन चर्चाओं को सुनकर उनकी आत्मा जरूर कलप उठती।

नियुक्ति प्रक्रिया कमाल की कही जाती है—

विज्ञापन निकाले जाते हैं, आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। बाबू स्तर के लोग पीएचडी और नेट-सेट वालों के दस्तावेजों की जाँच करते हैं। विशेषज्ञ सवाल पूछते हैं। फिर सब कुछ नियम-कायदे के अनुसार होता है।

यानी लोकतंत्र की पूरी बारात बैंड-बाजे के साथ तैयार रहती है, बस गोपनीय दुल्हे का खुलासा बाद में धीरे से ज्वाइनिंग के बाद होता है। न वेबसाइट में सूची अपलोड करने की जरूरत न वेटिंग वालों का नाम बताना जरूरी। वेटिंग में भी बड़े लोगों के शामिल रहने के मसले की बातें हैं।

कहा जाता है कि रेट में ऊपर तक का भी हिस्सा होता है।

यह “ऊपर” बड़ा रहस्यमय शब्द है।

न नक्शे में मिलता है, न नियुक्ति पत्र में, न किसी नियमावली में।

लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चाओं में यह हमेशा मौजूद रहता है।

एक नौजवान पाँच साल पीएचडी करता है। पाँच साल केवल कैलेंडर के पाँच पन्ने नहीं होते। उन पाँच वर्षों में घरवालों के सवाल होते हैं—

“नौकरी कब लगेगी?” दोस्त नौकरी पा चुके होते हैं, किसी की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और शोधार्थी अब भी पुस्तकालय में बैठा होता है। वह किताबों में डूबा रहता है, शोध करता है, रातों काटता है, डेटा जुटाता है, शोधपत्र लिखता है, संशोधन करता है, थीसिस जमा करता है। वाइवा देता है और एक दिन उसके नाम के आगे “डॉ.” लग जाता है। उसे लगता है—

अब मेरी योग्यता बोलेगी। फिर विश्वविद्यालय में एक पद निकलता है। वह आवेदन करता है, फाइल बनाता है, पीएचडी लगाता है, NET लगाता है, SET लगाता है, शोधपत्रों की सूची लगाता है, अनुभव प्रमाणपत्र लगाता है, किताबों की सूची लगाता है और फिर कहीं से खबर आती है—“भाई, योग्यता अपनी जगह है.. बाकी व्यवस्था अपनी जगह।” वह पूछता है—“बाकी क्या?” जवाब आता है—“आप समझदारी हैं।” बस, एक वाक्य में पाँच साल का शोध और पूरी व्यवस्था का दर्शन दोनों समाप्त।

यानी एक तरफ वषों का ज्ञान और दूसरी तरफ धन की क्षमता। फिर व्यवस्था खूबी है—“कौन अधिक योग्य है?” और अगर उत्तर पैसा है, तो फिर विश्वविद्यालय क्यों? खुली नीलामी क्यों नहीं? मंच पर उम्मीदवारों को बुलाइए और कहिए—“अपनी-अपनी बोलियाँ लगाइए।” जो सबसे ऊँची बोली लगाए।



उसे नियुक्ति पत्र दे दीजिए। कम से कम नाटक तो खत्म होगा। न इंटरव्यू का ढोंग, न दस्तावेज सत्यापन का अभिनय, न चयन समिति की गंभीर मुद्रा, न पारदर्शिता का भाषण। सीधी नीलामी—ज्ञान बाहर नकद अंदर और कुर्सी बीच में। कितनी सरल व्यवस्था होगी!

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास

लेकिन हम सभ्य समाज हैं। हम सीधे नीलामी नहीं करते। हम पहले विज्ञापन निकालते हैं, आवेदन लेते हैं, परीक्षा या स्क्रीनिंग करते हैं इंटरव्यू लेते हैं, दस्तावेज सत्यापन करते हैं, मेरिट बनाते हैं, चयन करते हैं और अगर कहीं नियुक्ति पहले से तय हो तो भी इन सारी प्रक्रियाओं को निभाते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को भी अब प्रोटोकॉल चाहिए।

यही तो आधुनिक पारदर्शिता है! सब कुछ पारदर्शी है—इतना पारदर्शी कि उम्मीदवार को भी पता है कि उसका चयन क्यों नहीं होगा, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सकता। और जिसे चयनित होना है, उसे शायद यह साबित करने की जरूरत भी नहीं।

विश्वविद्यालयों के पुराने आदर्श वाक्य होते थे—“तमसो मा ज्योतिर्गमय।” अर्थात् अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नए समय का आदर्श वाक्य शायद होना चाहिए—“निवेशं मा विलब्धय।” अर्थात् निवेश में विलंब मत करो, कहीं सीट किसी और की न हो जाए। यह व्यंग्य इसलिए जरूरी है कि विश्व की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति केवल वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं होता। वह विद्यार्थियों के सामने ज्ञान, योग्यता, नैतिकता और मेहनत का प्रतिनिधि भी होता है। अगर उसी कुर्सी तक पहुँचने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए, तो नुकसान केवल एक भर्ती का नहीं, पूरा शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का होता है।

अगर सचमुच किसी पद का भाव लायें रुपए में तय होने की बात सामने आती है, तो समस्या केवल इतनी नहीं कि एक नौकरा बिक रही है। समस्या यह है कि हमने ज्ञान के मंदिर में प्रवेश का टिकट ज्ञान से नहीं, कीमत से जोड़ दिया है और जिस दिन समाज यह मान लेता है कि नौकरा योग्यता से नहीं, कीमत से मिलती है, उस दिन केवल एक नियुक्ति भ्रष्ट नहीं होती। उस दिन आने वाली पूरी पीढ़ी को यह सिखाया जाता है कि मेहनत करना मूर्खता है और व्यवस्था को समझना ही असली योग्यता।

नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी और भारत के विकास का अगला चरण



श्रीमती निर्मला सीतारमण



‘विकसित भारत’ बनने के भारत के संकल्प के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें हर स्तर और आकार के उद्यम फल-फूल सकें, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। पिछले बारह वर्षों में हमारी सरकार ने इन अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान के लिए एक साझा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित हुआ। ‘नेक्स्ट-जेनरेशन का जीएसटी’ (Next-Gen GST) नौ वर्षों के क्रियान्वयन तथा करदाताओं और राज्यों के अनुभवों के आधार पर इसी प्रयास को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी की परिकल्पना दो परस्पर जुड़े उद्देश्यों के साथ की गई थी: कर दरों को कम व रकबसंगत बनाना और अनुपालन को अधिक सरल बनाना। दरों में किए गए संशोधन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए। प्रक्रियात्मक सुधारों का अगला चरण शीघ्र ही जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मिलित रूप से, इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को राहत देना, व्यवसायों को अधिक निश्चितता प्रदान करना और करदाताओं के लिए एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना है जिसमें वे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। राज्य इस पूरी यात्रा में बराबर के साझेदार रहे हैं। वे परिषद में अपनी प्राथमिकताओं और अनुभवों को लेकर आए, निर्णयों को आकार देने में सहयोग किया और उनके क्रियान्वयन का दायित्व संभाला। मैं इस प्रतिबद्धता के लिए उनका आधार व्यक्त करती हूँ। जीएसटी की प्रगति प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इसी तत्परता पर टिकी है। इसके परिणाम विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच, दर्ज की गई कर-योग्य आपूर्ति के मूल्य में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8% की वृद्धि हुई। कर दरों की हल्की संरचना के साथ-साथ दायीं गतिविधियों में भी व्यापक विस्तार देखा गया है। यह उस सुधार के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आधार है जिसका उद्देश्य उद्यमों और सार्वजनिक वित्त दोनों को संबल प्रदान करना है।

यह सुदृढ़ता हालिया राजस्व आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 12.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11.6% अधिक है। जून से सितंबर तक के प्रत्येक महीने में वार्षिक आधार पर दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई; इन चार महीनों का कुल संग्रह मिलकर लगभग 15% की गति से बढ़ा। कर वापसी (रिफंड) के बाद शुद्ध संग्रह में भी इस छमाही के दौरान 10.4% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, करदाताओं को दी गई राहत और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि साथ-साथ हुई है। इस विस्तार का दायरा उसके पैमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। सभी 11 क्षेत्रक समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में दर्ज कर-योग्य आपूर्ति में वृद्धि देखी गई। भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में यह व्यापक प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक हिस्सों में होने वाली यह वृद्धि अधिक से अधिक व्यवसायों को विस्तार लेते बाजारों में भाग लेने का अवसर देती है, और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मांग, निवेश तथा रोजगार से अधिकाधिक समुदायों को लाभान्वित करती है। सुधार के बाद की अवधि की तुलना में उपभोक्ताओं को की गई वस्तुओं की बिक्री (बी2सी) में भी 26.7% की बढ़ोतरी हुई। जब कर राहत का प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है, तो परिवारों के पास अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने या जुट कर करने के लिए अग्रणी गुंजाइश होती है। उपभोक्ता राहत और उद्यम विकास आपस में गहराई से बचते हैं: परिवारों की क्रय शक्ति वृद्धियों द्वारा दी जाने वाली रस्तुओं और सेवाओं की मांग को बनाए रखती है। इसका लाभ परिवार से लेकर खुदरा विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और उत्पादक तक सभी तक पहुंचता है। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय



बाजार तभी सार्थक होता है जब वह उनके स्थानीय परिवेश से परे ग्राहकों तक पहुँचने का व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करे। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के व्यवसायों को स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार जारी रखते हुए ऐसे संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, इन शहरों में विस्तार करने वाले उद्यम स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के लिए नए अवसर सृजित कर सकते हैं। जीएसटी का साझा ढांचा इन कड़ियों को सुदृढ़ करता है; और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को इन्हें बनाए रखना और भी सहज बनाना होगा। इस व्यवस्था में सहभागिता अत्यंत व्यापक रही है। अगस्त के अंत तक केंद्र और राज्य क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत कुल जीएसटी पंजीकरण लगभग 1.71 करोड़ तक पहुँच गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15% अधिक हैं। अप्रैल-जुलाई 2026 की कर अधियों के लिए, निर्धारित तिथि तक दाखिल किए गए जीएसटी-आर-3बी रिटर्न पिछले वर्ष की समान अवधियों की तुलना में 12.6% अधिक थे। ये सुधार प्रशासन और एक समान दायित्व भी डालते हैं: नियमित अनुपालन को विश्वसनीय सेवा, स्पष्ट मार्गदर्श और समस्याओं के समयबद्ध समाधान द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की कार्यप्रणाली इस अनुभव का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुधार उपरत आंकड़े दर्शाते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से चुकाई गई कर देयता का अनुपात बढ़ा है। जबकि कर-योग्य आपूर्ति के सापेक्ष संचित क्रेडिट में कमी आई है। यह उन व्यवसायों के लिए उत्साहवर्धक है जो पात्र क्रेडिट के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करते हैं। किसी छोटे उद्यम के लिए उसकी कार्यशील पूंजी ही यह तथ्य करती है कि वह कितनी सुगमता से कच्चा माल खरीद सकता है, कोई ऑर्डर पुरा कर सकता है और अपना काम हाथ में ले सकता है। कर वापसी (रिफंड) भी उतनी ही प्रासंगिक है। अप्रैल-सितंबर के दौरान लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि (रिफंड) रीबूट के रूप में लौटाई गई। व्यवसायों के प्रायः बकाये को वापस लौटाना एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली का अनिवार्य अंग है। इस प्रक्रिया में अधिक निश्चिन्ता और पूर्वानुमेयता उद्यमों को अधिक आत्मविश्वास के साथ खरीद और उत्पादन की योजना बनाने में सहायता करेगी। किसी कर्दता को देय रिफंड प्राप्त होने का अनुभव प्रशासनिक दक्षता का एक प्रमुख पैमाना होता है। राज्यों की राजस्व स्थिति भी अधिक सुदृढ़ हुई है। इस वर्ष अप्रैल-सितंबर के दौरान एककूट माल और सेवा कर (आईजीएसटी) निपटान में उनके हिस्से सहित राज्यों की कुल एसीजीएसटी प्राप्तियों में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। संसाधन बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश को गति प्रदान करते हैं, जिससे परिवारों और बच्चों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर परिवेश मिलता है।



शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी

नई दिल्ली। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य हैं, उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। अब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने के मामले में गिल ने सौरव गांगुली और एमएस धोनी की बराबरी कर ती है। भारत-वेस्टइंडीज 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए- उन्होंने पूरी सीरीज में 167 के औसत से 334 रन बनाए- उन्होंने सीरीज में दो शतक भी लगाए और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। यह सातवीं बार है जब गिल ने अपने करियर में यह अवॉर्ड जीता है- वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारतीय के लिए सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड सुचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 15 बार यह मुकाम हासिल किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो अपने करियर में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे- भारतीयों की सूची में शुभमन गिल, एमएस धोनी, सौरव गांगुली और युवराज सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। ये चारों बल्लेबाज अपने-अपने वनडे करियर में 7-7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीत चुके हैं। चौकाने वाला तथ्य यह है कि गिल ने अपने सभी 7 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पिछले 4 साल के भीतर जीते हैं।

GST चोरी पर नहीं होगी गिरफ्तारी?

नई दिल्ली। GST लागू होने के करीब 9 साल बाद टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, सरकार जीएसटी अधिकारियों को मिली गिरफ्तारी की शक्ति हटाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है तो GST से जुड़े मामलों में टैक्स अधिकारियों के पास सीधे गिरफ्तारी करने की मौजूदा शक्ति खत्म हो सकती है। इसके लिए GST कानून में संशोधन करना होगा और सरकार इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद के सामने ला सकती है। मौजूदा GST कानून के तहत गंभीर टैक्स अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी का प्रावधान है। खासकर फर्जी बिल बनाना, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और जानबूझकर टैक्स चोरी जैसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। CGST Act की धारा 69 के तहत कमिश्नर को गिरफ्तारी की मंजूरी देने का अधिकार है। इसके लिए अधिकारी के पास ये मानने का पर्याप्त आधार होना चाहिए कि व्यक्ति ने गंभीर GST अपराध किया है।

सोना-चांदी फिर सस्ते

नई दिल्ली। सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है. स्थानीय सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई. सोना 800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,800 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई. इसके साथ ही पिछले पूरे कारोबारी सप्ताह पर नजर डालें तो सोने और चांदी दोनों में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है. यानी अगर आप धनतेरस, दिवाली या शादी के लिए सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बाजार में भाव नीचे आया है. हालांकि, कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. आज सोना 1,49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, यानी 800 रुपए सस्ता हुआ है. वहीं, चांदी 2,24,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार पर है, यानी आज चांदी 1800 रुपए सस्ती हुई है।



खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग से तीसरा वनडे हारी टीम इंडिया

नई दिल्ली। 3 अक्टूबर, शनिवार के दिन भारतीय टीम को एक रिएलिटी चेक मिला। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी थी, लेकिन तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 352 रन का टारगेट चेज करके इतिहास रच दिया। यह ODI क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज रहा। कैरेबियाई कप्तान शाई ओर वेस्टइंडीज की जीत के सबसे शुभमन गिल और उनकी टीम की 351 रन के विशालकाय स्कोर



पुलने ने नाबाद 162 रन बनाए
वड़े हीरो रहे. आखिर कप्तान
हमें गलती हुई, जो भारतीय
को भी डिफेंड नहीं कर पाया.

मैच के बाद कप्तान गिल का कहना था कि स्लो-ओवर रेट का उन्हें डेथ ओवरों में खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर इसके अलावा भी की सारी गलतियाँ ही हैं, जिनकी वजह से भारत तीसरा ODI हार गया। तीसरे वनडे मैच में भारत की अनुभवहीन गेंदबाजी की पोल खुल गई। जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया ने डेथ ओवरों में बहुत 5 ओवरों में वेस्टइंडीज को 56 रन से बल्लेबाज कीज पर हरा, 30 गेंद असंभव नहीं है।

अर्शदीप सिंह के बिना उतरी टीम इंडिया ने डेथ ओवरों में बहुत खराब गेंदबाजी की। आखिरी 5 ओवरों में वेस्टइंडीज को 56 रन बनाने थे। जब शाई होप जैसा सेट बल्लेबाज क्रीज पर हो, 30 गेंद में पचास से अधिक रन बनाना असंभव नहीं है।

वैभव के समर्थन में उतरे कप्तान श्रेयस

नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 15 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान दिया है. अय्यर ने जो कहा वो हर एक क्रिकेट फैन को जेरू जानना चाहिए. एशियन गेम्स के सेमीफाइनल और फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की. वहीं संजु सैमसन तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में भी वैभव टीम इंडिया का हिस्सा होंगे. श्रेयस अय्यर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी में भारतीय क्रिकेट में बड़ा असर डालने की काबिलियत है. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले अय्यर ने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर वैभव के साथ क्रिकेट से



हटकर जिंदगी के बारे में बात करके एक निजी रिश्ता बनाने की कोशिश की है। अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होने के साथ ही सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अथर ने संकेत दिया कि इस युवा खिलाड़ी को बड़ी भूमिका देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।

वित्तीय मजबूती के बावजूद नए संकट का खतरा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद भारत की वित्तीय व्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई खतरा नहीं आएगा. RBI गवर्नर संजय महोत्रा ने वित्तीय स्थिरता को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि आज की मजबूत वित्तीय स्थिति यह गारंटी नहीं देती कि फ्यूचर में कोई खतरा नहीं आएगा. लंबे समय तक आर्थिक स्थिति स्थिर रहने पर लोग और संस्थाएं ज्यादा जोखिम लेने लग सकते हैं और कर्ज भी बढ़ सकता है. RBI गवर्नर संजय महोत्रा ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि अगला वित्तीय संकट जरूरी नहीं है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ही शुरू हो.



बदलते समय में साइबर अटैक, भू-राजनीतिक घटनाएँ और तकनीकी गड़बड़ियाँ भी वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे में इसका असर वित्तीय व्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों पर भी पड़ सकता है। RBI गवर्नर के मुताबिक, भू-राजनीतिक घटनाएँ, साइबर अटैक और दूसरे देश के असर जैसे कई वजहों के कारण वित्तीय संकट का खतरा बढ़ सकता है।

भू-राजनीतिक घटनाएं: दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं से वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है.

साइबर अटैक: साइबर हमले से बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

तकनीकी गड़बड़ी: किसी बड़ी तकनीकी समस्या का असर बैंक, वित्तीय संस्थानों और बाजारों पर पड़ सकता है.

दूसरे देशों का असर: एक देश में शुरू हुआ वित्तीय संकट दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है.

ज्यादा कर्ज और जोखिम: लंबे समय तक स्थिरता रहने पर लोग और संस्थान ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और कर्ज बढ़ सकते हैं।

बैंकों के अलावा इन क्षेत्रों पर भी नजर जरूरी

RBİ गवर्नर का कहना है कि वित्तीय स्थिरता सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है. ऐसे में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), शेयर बाजार, पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी सर्विस और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क को भी मजबूत रखना जरूरी है.

RBI के प्रोजेक्ट में उतरीं दो बड़ी कंपनियां

भारत में प्लास्टिक के नोट की तैयारी तेज

नई दिल्ली। भारत में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलिमर से बने नोट देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 और 20 रुपये के पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पॉलिमर करेंसी के लिए जरूरी सामग्री की सप्लाई को लेकर कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए धरौली कंपनी UFlex ने अमेरिका की Spectra सिस्टम्स के साथ मिलकर बोलो जंपा की है।

दरअसल, सरकार पहले ही 10 और 20 रुपए की पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे चुकी है। वहीं, पॉलिमर नोट को लेकर यह पहल ऐसे समय में हो रही है, जब दुनियाभर के कई देशों में प्लास्टिक आधारित करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन नोटों को मौजूदा कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ माना जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में पॉलिमर नोट को लेकर क्या तैयारी चल रही है और इसमें किन कंपनियों की भूमिका सामने आई है।



पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस प्रोजेक्ट के तहत पॉलिमर नोट बनाने के लिए जरूरी खास सामग्री की सप्लाई करने वाली कंपनियों को सलेक्ट किया जा रहा है. BOPP की एक खास पॉलीप्रोपाइलीन सामग्री की जरूरत है. इससे नोट की छपाई और स्थाई के बेहतर तरीके से चिपकने में मदद मिलेगी. प्रस्तावित खरीद के तहत करीब 68,000 रीम सामग्री की जरूरत बताई जा रही है, जिसमें 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए 34,000-34,000 रीम शामिल हैं.

UFlex और Spectra ने मिलकर लगाई बोली

जानकारी के मुताबिक, भारतीय पॉलिमर कंपनी UFlex ने अमेरिका की Spectra सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों ने मिलकर पॉलिमर नोट से जुड़े इस प्रोजेक्ट के लिए बोली जमा की है।

इस साझेदारी में UFlex की पॉलिमर बनाने की क्षमता और Spectra सिस्टम्स की बैंकनोट की सुरक्षा और पहचान से जुड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इस बोली में शामिल होने को लेकर UFlex से प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

RBI के प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है?

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने की है। यह कंपनी RBI की

आबादी

2000
2.1 करोड़2025
4.6 करोड़+आबादी के साथ बढ़ रहा
वर्कलोडरायपुर
दुर्ग-भिलाई
बिलासपुरसाहब...
हमारी भी
सुरक्षा की
जिम्मेदारी है...

थाना

जनसंख्या
दोगुनी...
लेकिन पुलिस बल
कितना बढ़ा ?

- राज्य पुलिस में 84 हजार से ज्यादा पद स्वीकृत
- वर्तमान में छगपु। में तकरीबन 20 हजार पद खाली
- राज्य में हर साल करीब 1.14 लाख अपराध दर्ज हो रहे
- रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर का तेजी से विस्तार हुआ
- नक्सलियों के खाल्ते के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी शुरू

नक्सल क्षेत्र से
पैरामिलिट्री की वापसी

जिलों में पुलिस बल की स्थिति

रायपुर

3650 स्वीकृत
2750 उपलब्ध
(900 पद खाली)आबादी: 40 लाख+
जरूरत: 5400

दुर्ग-भिलाई

2600 स्वीकृत
1990 उपलब्ध
(600+ पद खाली)आबादी: 15 लाख+
जरूरत: 2600+

बिलासपुर

1792 तैनात
387 पद खालीआबादी: 35 लाख+
जरूरत: अधिकमुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की आबादी दोगुने से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन पुलिस बल में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई। राज्य में हर साल औसतन करीब 1.14 लाख अपराध दर्ज हो रहे हैं। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जैसे शहरों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसका असर खासतौर पर आमजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर और पुलिस की ड्यूटी टाइम पर सीधा पड़ रहा है। राज्य में हर साल औसतन करीब 1.14 लाख अपराध दर्ज हो रहे हैं। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जैसे शहरों का तेजी से विस्तार हुआ है।



शहर सत्ता/रायपुर। राज्य पुलिस में 84 हजार से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें करीब 20 हजार पद खाली हैं। यानी लगभग हर चौथा पद रिक्त है। छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की कमी के बीच अब बस्तर से नक्सलियों के खाल्ते के बाद छत्तीसगढ़ से पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी भी शुरू हो गई है। ऐसे में लम्बे समय से फोर्स और नक्सलियों के बीच परेशान रहे लोगों को सुरक्षा, भरोसा भी दिलाना होगा। लेकिन, तैनाती के लिए जिला बल के पास पर्याप्त संख्या और संसाधन भी होना चाहिए। इनकी वापसी के बाद इन क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस पर बढ़ेगी, जबकि राज्य पुलिस पहले से ही बल की कमी से जूझ रही है।

इन इलाकों में लगेगा जिला बल

बड़ी तैनाती बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में रही है। इसके अलावा मोहला-मानपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम और गरियाबंद में भी केंद्रीय बल तैनात हैं। ये जवान 400 से ज्यादा कैपों में तैनात रहे हैं।

बस्तर में 400 से ज्यादा कैप, 52 हजार केंद्र के जवान

राज्य में करीब 52 हजार पैरामिलिट्री जवान तैनात रहे हैं। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 8 और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 4 बटालियन शामिल हैं। करीब 40 हजार सीआरपीएफ जवानों में से 30% को दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम भेजा जा चुका है। अगले दो महीनों में कुछ कंपनियों को जम्मू भेजने की तैयारी है।

भर्ती का प्रस्ताव भेजा है

राज्य में करीब 25% पुलिस फोर्स की कमी है। इसकी पूर्ति और भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। - अरुणदेव गौतम, डीजीपी छत्तीसगढ़

फोर्स बढ़ाने के साथ
वर्कलोड घटाना होगा

रिटायर्ड आईपीएस अन्वेष मंगलम के मुताबिक देश के अधिकांश राज्यों में पुलिस बल की कमी है। आबादी और वर्कलोड के अनुपात में फोर्स उपलब्ध नहीं है, जबकि पुलिस की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कई तरह के कामों में लगती है। थानों के स्टाफ का बड़ा हिस्सा वीआईपी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त रहता है। इससे अपराधों की विवेचना के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। साइबर क्राइम भी बड़ी चुनौती बन चुका है।

साइबर अपराधों से मुकाबले में युवा बनें 'साइबर एम्बेसडर': वित्त मंत्री

रायगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत लघु फिल्म प्रतियोगिता का समापन, 11 राज्यों के 35 जिलों से मिली 162 प्रविष्टियां



रायपुर। साइबर अपराधों के प्रति आमजन, विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता का समापन एवं सम्मान समारोह रायगढ़ के पूज्य संत बाबा प्रियदर्शी रामजी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा रायगढ़ पुलिस द्वारा तैयार साइबर अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म 'The Cyber Trap' की स्क्रीनिंग की गई।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों की चुनौती भी बढ़ी है। इससे बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वयं

साइबर जागरूक बनें और 'साइबर एम्बेसडर' की भूमिका निभाते हुए अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करें।

श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में संचालित 'सेवा संकल्प अभियान' की चिन्हित सेवा गतिविधियों में साइबर जागरूकता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रायगढ़ पुलिस ने सिनेमा और रचनात्मकता को साइबर सुरक्षा से जोड़कर युवाओं तक प्रभावी संदेश पहुंचाने की अभिनव पहल की है।

कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल ने साइबर जागृति अभियान और तकनीक आधारित जनजागरूकता पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

और आधुनिक तकनीक का उपयोग जनहित, जागरूकता और सुरक्षा के लिए किया जाना समाज को अधिक सुरक्षित बनाने में प्रभावी साबित हो सकता है।

सात सप्ताह में करीब 2 लाख लोगों तक पहुंचा अभियान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेशव्यापी 'साइबर जागृति अभियान' संचालित किया गया। सात सप्ताह के दौरान रायगढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियों और माध्यमों से करीब 2 लाख लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसी अभियान के अंतर्गत 'संकल्प : साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़' थीम पर लघु फिल्म प्रतियोगिता

आयोजित की गई। इसका उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता को साइबर जागरूकता से जोड़कर डिजिटल सुरक्षा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था।

रूस से भी आई प्रविष्टि

प्रतियोगिता को देशभर से व्यापक प्रतिसाद मिला। देश के 11 राज्यों के 35 जिलों से कुल 162 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों के साथ रूस से भी एक फिल्म की प्रविष्टि प्राप्त हुई। प्रतियोगिता के आयोजन में रोटरी क्लब रायगढ़ का विशेष सहयोग रहा, जबकि प्रबंधन की जिम्मेदारी Take 3 Studios द्वारा संभाली गई। प्रतियोगिता के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित फिल्मकारों को निर्णायक मंडल में शामिल किया गया। इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'भूलन: द मेज' के निर्देशक श्री मनोज वर्मा, फिल्मकार श्री योगेंद्र चौबे तथा रंगकर्मी, फिल्म अभिनेता, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार एवं अभिनय प्रशिक्षक श्री सुनील चिपड़े शामिल रहे।

'दूसर छोर' और 'एक्सेस लिंक' ने हासिल किया प्रथम स्थान

प्रतियोगिता की श्रेणी 'अ' (3 से 6 मिनट) में स्वपनिल कोटरीवार की फिल्म 'दूसर छोर' ने प्रथम, होमेट्रु कुमार की फिल्म 'जरूरत' ने द्वितीय तथा प्रकाश पटेल की फिल्म 'गुपचुप ठेला' ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्रेणी 'ब' (1 से 3 मिनट) में दीपक जायसवाल की फिल्म 'एक्सेस लिंक' प्रथम, तुषार सोलंकी की फिल्म 'Dial 1930' द्वितीय और समीर चन्द्रा की फिल्म 'Golden Hour' तृतीय स्थान पर रही। श्रेणी 'अ' के प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 75 हजार रुपए और तृतीय विजेता को 50 हजार रुपए प्रदान किए गए। श्रेणी 'ब' में प्रथम विजेता को 75 हजार रुपए, द्वितीय को 50 हजार रुपए तथा तृतीय विजेता को 25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के छह विजेताओं को कुल 3.75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।

'The Cyber Trap' के जरिए बताए साइबर अपराध से बचाव के तरीके

समारोह में रायगढ़ पुलिस द्वारा विशेष रूप से तैयार साइबर अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म 'The Cyber Trap' की स्क्रीनिंग की गई। यह फिल्म प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों को साइबर अपराध के नए तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अलग से तैयार की गई है। फिल्म में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित अनिल सोनी, मयंक मिश्रा, उत्तम प्रताप सिंह, राकेश मिश्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, सानिया गुप्ता, लीना ठाकुर, दिपेश महंत, हर्ष बैरागी तथा रायगढ़ पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों ने भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी एवं निर्देशन श्री ऋषी समर्थ सिंह ने किया है। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, महापौर जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, प्रतिभागी, शिक्षक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।